



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

15 दिसंबर 2021

आरबीआई बुलेटिन - दिसंबर 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपने मासिक बुलेटिन का दिसंबर 2021 का अंक जारी किया। बुलेटिन में गवर्नर का वक्तव्य; मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 दिसंबर 2021; विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य; दो भाषण; चार लेख; और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

चार आलेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. सरकारी वित्त 2021-22: अर्ध-वार्षिक समीक्षा; III. भारत के परिधान निर्यात में क्या दिक्कत है?; और IV. कोयला आपूर्ति-मांग की स्थिति और प्रभाव।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़ी हुई अनिश्चितता की बंधक बनी हुई है, जिसमें ओमीक्रोन ने नए रोकथाम उपायों को बढ़ावा दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने ति2: 2021-22 में जोरदार वापसी की, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद अपने पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया, और मुद्रास्फीति मोटे तौर पर लक्ष्य के साथ संरेखित हो गई। आने वाले उच्च आवृत्ति संकेतकों का एक दल उत्साहित दिख रहा है और उपभोक्ता विश्वास धीरे-धीरे लौट रहा है। कुल मांग की स्थिति निरंतर सुधार की ओर, हालांकि, क्रमिक सुधार के कुछ संकेतों के साथ इशारा करती है। आपूर्ति पक्ष पर, रबी की बुवाई की प्रभावशाली प्रगति के साथ कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जबकि विनिर्माण और सेवाओं ने मांग की स्थिति को मजबूत करने और नए व्यवसाय में उछाल पर मजबूत सुधार दर्ज किया है।

II. सरकारी वित्त 2021-22: अर्ध-वार्षिक समीक्षा

श्रृंखला में चौथा लेख, तिमाही आवृत्ति पर, सरकारी वित्त - केंद्र, राज्य और संयुक्त की मध्य-वर्ष की समीक्षा प्रस्तुत करता है।

मुख्य बातें

- सरकारी वित्त ने महामारी की दूसरी लहर के प्रति उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। कर संग्रह ने उम्मीदों को पार कर लिया है, केंद्र के सभी शीर्ष कर प्रमुखों ने एच1:2021-22 में एक मजबूत वृद्धि दर्ज की है। राज्यों के कर संग्रह ने भी एक मजबूत वृद्धि को दर्शाया है और एच1:2021-22 में पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच गया है।
- अतिरिक्त व्यय भार के बावजूद, सरकारी व्यय मोटे तौर पर बजट अनुमानों के अनुरूप रहा है और व्यय की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

- आगे, जबकि कर राजस्व में उछाल रहने की उम्मीद है, सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा, जो एच1:2021-22 में कम रहा, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि में संवृद्धि के समर्थन और उसे बनाए रखने के लिए व्यय में सुधार का समय देता है।

III. भारत के परिधान निर्यात को क्या नुकसान पहुंचता है?

भारत को पारंपरिक रूप से परिधान सहित कपड़ा क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुआ है, और वे भारत के निर्यात बास्केट का एक बड़ा हिस्सा हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, भारत के कपड़ा निर्यात, विशेष रूप से परिधान निर्यात में लगभग ठहराव देखा गया है। यह लेख भारत सहित प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से परिधानों के निर्यात को निर्देशित करने में गंतव्य देश की टैरिफ व्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण करता है।

मुख्य बातें

- यूरोपीय संघ को भारत का परिधान निर्यात, जो परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है, पिछले एक दशक में स्थिर हो गया है जबकि बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे अन्य देशों में मजबूत वृद्धि देखी गई है।
- ईबीए (शस्त्र को छोड़कर सब कुछ) के रूप में अधिमान्य टैरिफ प्रबंध बांग्लादेश और कंबोडिया से परिधान निर्यात के तेजी से विकास के लिए एक प्रमुख योगदान कारक रहा है, विशेषकर 2011 में इनपुट सोर्सिंग मानदंडों में छूट के बाद।
- समान टैरिफ संरचना का सामना करने के बावजूद वियतनाम द्वारा यूरोपीय संघ को परिधान निर्यात में मजबूत वृद्धि भारत में परिधान निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे कुछ अंतर्निहित मुद्दों को दर्शाती है।

IV. कोयला आपूर्ति-मांग की स्थिति और प्रभाव

यह लेख वैश्विक और घरेलू कारकों के कारण भारत में कोयला क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई हालिया मांग-आपूर्ति बेमेल का विश्लेषण करता है। कोयला ताप विद्युत और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट होने के कारण, इसकी सामयिक और पर्याप्त आपूर्ति अनिवार्य है। सरकार के प्रयासों से हाल के हफ्तों में कोयले की कमी कम हुई है।

मुख्य बातें

- घरेलू आपूर्ति में व्यवधान और आयात में कमी दोनों के कारण, कोयले की मांग-आपूर्ति संतुलन विशेष रूप से ताप विद्युत क्षेत्र के मामले में पिछले कुछ महीनों में खराब हो गया है।
- सितंबर के महीने और अक्टूबर की शुरुआत में भारी बारिश के कारण कोयला बहुल क्षेत्रों में जलभराव ने कोयला खदानों से प्रेषण में बाधा उत्पन्न की; अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण कोयले के आयात में कमी के कारण भी मांग-आपूर्ति में बेमेल देखा गया।
- सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त स्टॉक बनाने के लिए कोयले की आपूर्ति में तेजी लाई है और हाल के सप्ताहों में इस स्थिति में काफी सुधार आया है।

- ऊर्जा की मांग में वृद्धि के कारण वैश्विक कोयले की मांग भी 2021 में बढ़ी क्योंकि यह कुल विश्व ऊर्जा के खपत का एक बड़ा हिस्सा है।
- मध्यम से दीर्घावधि में, ऊर्जा के हरित स्रोतों में वृद्धि से भारत की कोयले पर निर्भरता कम होगी और ग्लासगो में COP26 में भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1363

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक